

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 246 / 2022

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 वगतावनसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 75 वर्ष	1 धन्नाराम पुत्र रूगाराम उम्र 67 वर्ष
2 त्रिखमसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 73 वर्ष	2 दीपाराम पुत्र रूगाराम उम्र 60 वर्ष
3 पोकरसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 70 वर्ष	जाति दर्जी निवासी सोढों की ढाणी हाल
4 बाबूसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 60 वर्ष	जसोल तहसील पंचपदरा जिला बाडमेर
जाति राजपुत निवासी सोढों की ढाणी	3 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक
तहसील सिणधरी	शाखा सिणधरी
5 दरियाकवर पुत्री हरदानसिंह पत्नि	4 तहसीलदार, सिणधरी जिला बाडमेर
रतनसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपुत निवासी	
धनदा तहसील सिणधरी	
6 नथूकवर पुत्री हरदानसिंह पत्नि मोडसिंह	
उम्र 63 वर्ष निवासी बालोतरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

## निर्णय

दिनांक- 11.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण पैतृक कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में स्थित है जो अकेले प्रार्थीगण पिता के खातेदारी का था तथा हरदानसिंह के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के पैतृक खातेदारी अधिकारों की थी। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में के पिता हरदानसिंह के साथ प्रार्थीगण जो हरदानसिंह के जायदा पुत्र व पुत्रीयां है, के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके हैं, जिससे प्रार्थीगण व उनके पिता हरदानसिंह का वादग्रस्त भूमि में 1/7-1/7 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के मध्य भूमि का बाहामी बंटवाडा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की सहदायिकी सम्पत्ति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं था तथा समस्त भूमि



राजस्थान सरकार  
SDO सिणधरी

गण के पिता हरदानसिंह के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, जिसका प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह ने नाजायज फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि में अपने 1/7 हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान अजनबी व झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्तियों विप्रार्थी संख्या 1 व 2 रूगाराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 6 के कर दिया है जिस संबंध में प्रार्थीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही प्रार्थीगण को कोई जानकारी दी गई तथा प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह ने गुप्त रूप से अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान प्रार्थीगण के हिस्से सहित कर दिया है जो बेचान प्रार्थीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा प्रार्थीगण स्व हरदानसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये था। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप प्रार्थीगण विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। बादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि आगे से आगे हस्तांतरण करने पर प्रयासरत है तथा अब प्रार्थीगण को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते हैं तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी कर रहा है। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण विधिक हिस्सा 1/7-1/7 है तथा इसी हिस्से की घोषणा खातेदारी एवं विभाजन का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही किसी प्रकार का बेचान, हस्तांतरण आदि नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति यथावत रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण पैतृक कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में स्थित है जो अकेले प्रार्थीगण पिता के खातेदारी का था तथा हरदानसिंह के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के पैतृक खातेदारी अधिकारों की थी। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में के पिता हरदानसिंह के साथ प्रार्थीगण जो हरदानसिंह के जायंदा पुत्र व पुत्रीयां है, के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके हैं, जिससे प्रार्थीगण व उनके

पंजी  
रजिस्ट्रार  
200 निम्न

श्रीता हरदानसिंह का वादग्रस्त भूमि में 1/7 1/7 हिस्सा पैतृक खानेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के मरु भूमि का बाहामी बंटवाहा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवाली दाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की सहदायिकी सम्पत्ति होने परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं होने से प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह ने ना-जायज फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि में अपने 1/7 हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान को प्रार्थीगण के एक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्धता रखता हो, जिसका निस्तारण मूलवाद में सख्त सबूतो के आधार पर निर्धारित होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीनीगण का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रादली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर एवं नम्बर से कम हो।



(प्रमोद कुमार)

**उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणघरी**

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



**उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणघरी**